

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'संकल्प से सिद्धि' के विचार देश के सामने रखे थे, जिनके सुख परिणाम हमें दिखायी दे रहे हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरत का संकल्प लिया था, जिसकी पूर्ति हेतु रक्षा उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करके अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस संर्दृग्रंथ में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 में भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो एक कीर्तिमान है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में बीते वर्ष 16.7 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्हां कहा भी है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान साल-दर-साल नये-नये मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया था, जिसकी पूर्ति हेतु रक्षा उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करके अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ाया दिया गया। इस संर्दृ में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 में भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो एक कीर्तिमान है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वीते वर्ष 16.7 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही कहा भी है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान साल-दर-साल नये-नये मील के पथ्यर स्थापित कर रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम तो अनेक क्षेत्रों में दिख रहे हैं, पर रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का एक विशिष्ट महत्व है। ऐतिहासिक रूप से हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहे हैं। कुछ वर्षों से भारत सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि हमारी सेनाएं कई वस्तुओं की खरीद देश में ही करेंगी। इन वस्तुओं की सूची लगातार बड़ी होती जा रही है। बड़ी आयुध सामग्री के निर्माण में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत में युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण भी हो रहा है। स्मरण रखें कि इनके निर्माण की क्षमता कुछ गिने-चुने देशों के पास ही है। इसलिए यह विशेषताएँ पर

उल्लेखनीय है। आयात घटने और निर्यात बढ़ने से खर्च में कमी आ रही है और रक्षा उद्योग की कमाई में बढ़तरी हो रही है।

विभिन्न सुधारों के परिणाम उत्साह जनक है। वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रहा, जो अभूतपूर्व है। साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रहा था। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि की गति के बने रखने की पूरी संभावना है, जिसका एक संकेत हमें शेरयर बाजार में संबंधित कंपनियों के प्रदर्शन से मिलता है। इसे ठास आधार देने के लिए शोध एवं अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम अत्याधुनिक तकनीकी आधारित साज़ों-सामान का उत्पादन बढ़ा सकें।

कुछ अलग एआइ पर बड़ी पहल

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। इसके साथ-साथ इसके दुरुपयोग और कुप्रभावों को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआइ के मामले में भारत सरकार दो पहलुओं पर काम कर रही है—इसकी क्षमता को बढ़ाना तथा सुरक्षा के उपाय करना। बीते मार्च में कैबिनेट ने 'इंडिया एआइ मिशन' को स्वीकृति दी थी। अगले दो-तीन महीनों में दो मिशन को पारंपरिक दिव्याज्ञानों

The image is a composite of two photographs. On the left, a blue-tinted silhouette of a human head is shown against a dark background. On the right, there is a glowing blue circular interface, possibly from a computer screen, featuring the words "Artificial Intelligence" and a stylized AI icon.

एआइ पर बड़ी पहल

अलग

कारगिल के सबक दूर करेंगे अविनपथ की खामियां

कारगिल

दुनीया से

कारगिल के सबक दूर करेंगे अधिनपथ की ख

कारगिल

युद्ध (1999) में 4 जुलाई का बड़ा महत्व है, इस दिन इस युद्ध के क्रियान्वयन एवं राजनीतिक पहलुओं पर गोष्ठियां आयीं जित होती हैं। इस बार, वर्तमान चुनौती-अधिनपथ योजना- के बीच चले विमर्शों ने ऊँचाई वाले रणक्षेत्र के रक्षा प्रबंधन तंत्र में सुधार हेतु महत्वपूर्ण उपाय पेश किए हैं। क्रियान्वयन के स्तर पर, टाइगर हिल (16,606 फीट) पर 18वीं प्रेनेडियर बटालियन की 'घातक' पलटन द्वारा किया कब्जा भारत के लिए निर्णायक मोड़ बाला रहा, पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल परवेज मुशर्रफ को इस नुकसान से भान हो चला था कि यह उनके बेवकूफाना दुस्साहस के अंत की शुरुआत है। राजनीतिक स्तर पर, तकालीन पाकिस्तानी पार्टीजनीलताओं ने अपेक्षिती पार्टीयां में वापिसी आक्रमणों से बचाव की तैयारी की है।

वाशिंगटन डिसी में तत्काल
मुलाकात के लिए समय मांगा,
इसका परिणाम स्पष्ट था। जहां
नवाज शरीफ की इच्छा अमेरिकी
दखल से भारत को संयमित
करवाने की थी वहीं किलंटन का
संदेश एकदम दृढ़ था 'पाकिस्तानी
फौजियों को वास्तविक नियंत्रण
सीमा के पार, वापस अपनी पुरानी
जगह पर लौटना होगा।' लाचार हुए
पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पास इस
सलाह को मानने के अलावा कोई
अन्य चारा न था, यह थप्पड़
रावलपिंडी के पाकिस्तानी सेना
मुख्यालय में बैठे जनरलों के मुंह पर
भी अपमान का तमाचा था।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जनरलों को राष्ट्रपति से पारागिल-1999
डीसी में तत्काल मुलाकात के लिए समय मांगा, इसका
परिणाम स्पष्ट था। जहां नवाज शरीफ की इच्छा अमेरिकी
दखल से भारत को संयमित करवाने की थी वहीं किलंटन का
संदेश एकदम दृढ़ था 'पाकिस्तानी फौजियों को वास्तविक
नियंत्रण सीमा के पार, वापस
अपनी पुरानी जगह पर
लौटना होगा।' लाचार हुए
पाकिस्तान प्रधानमंत्री के
पास इस सलाह को मानने के
अलावा कोई अन्य चारा न
था, यह थप्पड़ रावलपिंडी के
पाकिस्तानी सेना मुख्यालय
में बैठे जनरलों के मुंह पर भी

अपमान का तमाचा था। हालांकि, आधिकारिक रूप से युद्ध
26 जुलाई को समाप्त घोषित हुआ था, जिसे भारत में 'विजय
दिवस' के रूप में मनाया जाता है और संभावना है कि भाजपा
नीत एनडीई गठबंधन की सरकार इस अवसर की 25वीं
वर्षगांठ को विशाल स्तर पर मनाएगी। इस लड़ाई के
परिणामों को गहराई से आकलन और विमर्श, भारत की
मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में इनकी
प्रासंगिकता की अहमियत पर पुनर्विचार करने का आह्वान
करते हैं। वर्ष 1999 के युद्ध साल को कई वजहों से त्रिकोणीय
कहा जा सकता है— मसलन, चाहे यह 'परमाणु परछाई'

(भारत और पाकिस्तान, दोनों ने, मई 1998 में अपनी
परमाणु समर्था का प्रदर्शन किया) या दिसम्बर, 1991 में
महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कारगिल
युद्ध इस उप-महाद्वीप का पहला बड़ा संघर्ष था या फिर इस
तथ्य के महेनजर कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी

करता है। वे त्रिवर्तकालीन प्रधान
हैं कि उन्होंने 29 जुलाई, 1999 के
के सुबहमण्यम के नेतृत्व में एक से
जिसको काम सौंपा गया— जम्मू-कश्मीर
कारगिल में पाकिस्तानीयों की सुरक्षा
पड़त प्रकार
राष्ट्रीय
वाले
आवाज
विशेष
कार्य
समय
दिसम्बर
पूरा कर दिखाया— तथ्यमुदा सीमा से
23 फरवरी, 2000 को कारगिल
गई। तुरंत बाद, यह रिपोर्ट बतौर एक
हिस्से की कांट-छांट के बाद सावधान
हुई। 'कारगिल-1999' नामक यह
पारदर्शितापूर्ण है जबकि अक्तूबर,
मिली अभागी हार की समीक्षा में ऐसे
नेहरू से लेकर मोदी तक आए, कि
निश्चय नहीं दिखाया कि हेंडॉ
सार्वजनिक रूप से जारी किया जा
दस्तावेज साइबर स्पेस पर उपलब्ध
विजय के 25 साल बाद, यह शर्म
समीक्षा समिति द्वारा सुझाई मुख्य हिं
में न तो विमर्श हुआ न ही संवेदन
विस्तारित और रचनात्मक ढंग से इ



नयी सरकार के पहले बजट से उम्मीदें

सम्प्रे

